

उत्पत्ति/ Genesis

जनजाति समुदाय अपनी आजीविका हेतु मुख्य रूप से कृषि, वन और पशुधन पर निर्भर है. देश के कई हिस्सों में, जनजाति समुदाय अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं और सड़क एवं संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल जैसी सामान्य आधारभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं, जो उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी और वित्तीय सुविधाओं को अवशोषण करने की अनुमति नहीं देती है. नाबार्ड जनजाति परिवारों, संवर्धनात्मक गतिविधियों आदि को सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों को ऋण की अलग व्यवस्था के माध्यम से जनजातीय विकास सहायता प्रदान करता रहा है. तथापि, नाबार्ड के लिए जनजाति आजीविका की संधारणीयता एक प्रमुख चिंता रही है. नाबार्ड ने गुजरात और महाराष्ट्र में केएफ़डब्ल्यू से सहायता प्राप्त आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इस दिशा में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है. आदिवासी विकास कार्यक्रमों के सफल अनुभव के आधार पर, नाबार्ड ने देश भर में स्मॉल ऑर्चर्ड मॉडल को दोहराने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया. इस दिशा में, नाबार्ड ने 2003-04 में अपने लाभ में से रु.50 करोड के कॉरपस के साथ जनजाति विकास निधि (टीडीएफ़) का सृजन किया. केवीके, एनजीओ और कॉर्पोरेट के साथ भागीदारी द्वारा टीडीएफ़ के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया. इस कार्यक्रम के तहत जनजातियों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कृषि संबद्ध गतिविधियों सहित बगान विकास को शामिल करते हुए व्यापक जनजाति विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है.

The tribal communities are dependent mainly on agriculture, forests and livestock for their livelihood. In many parts of the country, the tribal communities reside in inaccessible areas and are still devoid of common infrastructure facilities such as road and communication, health, education and safe drinking water, which do not allow them to absorb technological and financial facilities provided by government. NABARD has been supporting tribal development through, separate line of credit to agencies supporting tribal families, promotional activities, etc. However, a key concern for NABARD has been the sustainability of tribal livelihoods. NABARD gained rich experience in this direction through implementation of KfW assisted Adivasi Development Programmes in Gujarat

and Maharashtra. Based on the successful experience of Adivasi Development Programmes, NABARD embarked upon an ambitious program of replicating the small orchard model across the country. In this direction, NABARD created a Tribal Development Fund (TDF) with a corpus of Rs.50 crore, out of its profits in 2003-04. All projects under TDF are implemented by partnering with KVKs, NGOs and Corporates. The comprehensive tribal development programme, including orchard development along with agri. allied activities is being implemented for improving livelihood of tribals under this programme.